Construction of Court buildings

*36. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Union Government have taken a decision to provide assistance to the State Governments for construction of buildings both official and residential covering High Courts and District Courts on 50-50 basis;

(b) if so, the details thereof, Statewise;

(c) the details regarding proposals received from each State as on date;

(d) whether the Union Government propose to make any financial provision for this purpose during 1994-95, Statewise;

(e) whether there is any proposal from Gujarat and Maharashtra for the purpose and if so, the decision taken thereon; and

(f) if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) to (f) The Centrally Sponsored Scheme approved by the Government relating to infrastructural facilities for the Judiciary includes construction of official and residential buildings for District Courts and High Courts. The expenditure on the scheme is to be shared by the Central and State Governments on 50:50 basis. Expenditure in respect of the Union Territories is to be met fully by the Centre.

The State Governments were asked to send their proposals for the Eighth Five Year Plan alongwith the physical and financial parameters for the Annual Plan of 1994-95. The proposals received from the States (including Gujarat and Maharashtra) in respect of admissible items of expenditure for 1994-95 are given in the enclosed statement -I (See below).

The amounts of Central share allocated to various States during 1994-95 given in the enclosed statement-II.

(Rs. in lakes)

Name of the States	Financial proposals received for 1994-95
1. Assam	204.15
2. Bihar	400.00
3. Gujarat	1720.60
4. Goa	300.00
5. Haryana	2589.50
6. Himachal Pradesh	1862.34
7. Jammu & Kashmir	1760.00
8. Karnataka	3220.40
9. Kerala	1604.67
10. Madhya Pradesh	380.00
11. Maharashtra	2834.38
12. Manipur	422.20
13. Mizoram	138.04
14. Nagaland	304.50
15. Punjab	2500.00
16. Meghalaya	34.0
17. Sikkim	167.74
18. Tamil Nadu	1265.27
19. Tripura	1571.82
20. Uttar Pradesh	12844.66
21. West Bengal	338.00
22. Orissa	271.50
23. Andhra Pradesh	211.00

Statement ....

Amount tentatively allocated to various States under the Centrally Sponsored Scheme during 1994-95

Sl. No.	Name of the State	Amount allocated (Rs. in lakhs)
1.	Andhra Pradesh	378.6
2.	Arunachal Pradesh	34.0
3.	Assam	135.0
4.	Bihar	294.3
5.	Goa	34.0
6.	Gujarat	169.9
7.	Haryana	81.0
8.	Himachal Pradesh	34.0
9.	Jammu & Kashmir	34.0
10.	Karnataka	246.7
11.	Kerala	164.4

12. Madhya Pradesh	302.6
13. Maharashtra	324.7
14. Manipur ..	34.0
15. Mizoram	54.0
16. Mekhalaya	34.0
17. Orissa	193.0
18. Punjab	86.8
19. Rajasthan	233.1
20. Sikkim	34.0
21. Nagaland	34.0
22. Tamilnadu	326.5
23. Tripura	34.0
24. Uttar Pradesh	723.0
25. West Bengal	487.5
TOTAL:	4488.0

औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में पंजीकृत उत्तर प्रदेश की रुग्ण इकाईयां

*37. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या प्रधान मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 नवम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में पंजीकृत उत्तर प्रदेश की रुग्ण औद्योगिक इकाईयां कौन-कौन सी हैं ;

(ख) किस राज्य में सर्वाधिक रुग्ण औद्योगिक इकाईयां हैं; और

(ग) इन इकाईयों को व्यवहार्य बनाने की क्या योजनायें हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई० एफ०आर०) के अनुसार 31-10-94 को उनके पास पंजीकृत हुए उत्तर प्रदेश के रुग्ण एककों के मामलों की संख्या 157 है। इनमें 32 मामले समर्थन योग्य नहीं पाये गये थे, 27 मामलों के लिए पुनर्स्थापना योजनाएं स्वीकृत/अनुमोदित/क्रियान्वित की गई थी और 36 मामलों को बन्द करने की सिफारिश की गई थी।

(ख) बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किये जाते हैं। सितम्बर, 1992 के अंत तक की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश राज्य में रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की संख्या सर्वाधिक है।

(ग) सरकार ने रुग्ण तथा बन्द औद्योगिक एककों को फिर से चालू करने के लिए कई उपाय किये हैं। उनमें से कुछेक महत्वपूर्ण उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

रुग्ण औद्योगिक एककों को फिर से चालू करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय।

सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात् रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष अनुबन्ध) अधिनियम, 1985 बनाया है। इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०)" नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारंभिक अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने हेतु बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किये जा सकें।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्यक्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने